C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 246 नागपुर, बुधवार, 2 अगस्त 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से अरविंद पनगढ़िया का इस्तीफा

नई दिल्ली

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 31 अगस्त तक आयोग को अपनी सेवाएं देंगे। पनगढ़िया ने फिलहाल अध्यापन में वापसी करने की बात कहकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनने के बाद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। देश की नीति और विकास प्रक्रिया को नई दिशा देने के लिए मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की शुरुआत की थी।

हालांकि अभी तक पनगढ़िया के इस्तीफा देने के सही कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने अपने फैसले से पीएमओ को भी अवगत करा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल असम के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं। लिहाजा उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने वाले 62 वर्षीय पनगढ़िया को प्रधानमंत्री मोदी ने ही नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के तौर पर चुना था।

पनगढ़िया की पहचान दुनिया के अनुभवी अर्थशास्त्री में होती है। उन्हें पांच जनवरी, 2015 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले वह एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं। इसके अलावा वह वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और अंकटाड में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली है। अभी तक के जीवन में पनगढ़िया करीब 10 किताबें लिख चुके हैं।

जनता में पहुंच बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने किया विभागों का गठन

नई दिल्ली

जनता में पहुंच बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने नया कदम उठाया है। कांग्रेस ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों के साथ-साथ पेशेवरों तक पहुंचने के लिए दो नए संगठनात्मक विभाग तैयार किए हैं। अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस विभाग का गठन किया गया है, जिसे पार्टी सांसद शशि थरूर तथा दूसरा अखिल भारतीय असंगठित श्रमिक कांग्रेस, जिसका नेतृत्व अरविंद सिंह करेंगे। पार्टी रिलीज में बताया गया है कि इरफान आलम असंगठित श्रमिक कांग्रेस के उपाध्यक्ष होंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) में दो और संगठनात्मक विभाग बनाने के सुझाव को मंजूरी दी है। साझ सोनिया गांधी ने पार्टी के मछुआरे विभाग का नाम अखिल भारतीय मछुआरे कांग्रेस में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

मेघालय में 8 पुलिस वाहनों में लगी आग, पुलिस जांच में जुटी

मेघालय

मेघालय के पुलिस हेडक्वार्टर में भयंकर आग लगने से 8 वाहन जलकर खाक हो गए। इनमें तीन दुपहिया वाहन भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन में आग लगने के सही कारण पुलिस पता लगा रही है। आग लगने से पुलिस की पांच जिप्सी, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटर जलकर खाक हो गया है। आग लगने का पता चलने के बाद कुछ कर्मियों ने अलार्म बजाया जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग किन कारणों से लगी है।

अभिवादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि निमित्त गिरगांव चौपाटी स्थित लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पण कर अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं इस मौके पर उपस्थित मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, विधायक आशीष शेलार एवं अन्य मान्यवर।

शाहिद अब्बासी बने पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री, 221 वोटों से जीता चुनाव

नई दिल्ली

शाहिद खाकान अब्बासी मंगलवार को पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री चुन लिए गए। अब्बासी ने 221 वोटों से प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। पाकिस्तानी संसद ने अब्बासी को निर्विरोध उम्मीदवार चुना है। इस चुनाव के लिए पीएमएल-एन के अब्बासी समेत कुल 6 कैंडिडेट मैदान में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से खुर्शीद शाह और नावेद कमर का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए घोषित किया गया था।

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने शेख राशिद को अपनी ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक किसी पार्टी के उम्मीदवार को बहुमत के लिए 172 वोटों की जरूरत होती है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पनामा मामले में दोषी करार दिया और उन्हें पीएम पद के लिए अयोग्य करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के दोषी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से शाहिद खाकान अब्बासी को अंतरिम पीएम बना दिया गया।

दिग्विजय सिंह तेलंगाना में कांग्रेस प्रभारी पद से हटाए गए

नई दिल्ली

कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह से तेलंगाना के पार्टी प्रभारी पद की जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। पार्टी ने मंगलवार को यह दायित्व आरसी खुंटिया को सौंप दिया।

कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआइसीसी की नई टीम बनाने का निर्णय लिया है जो तेलंगाना में पार्टी के मामलों को देखेगी।

दिग्विजय सिंह को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि पार्टी सेक्रेटरी के रूप में सतीष जर्किहोली खुंटिया के सहायक होंगे। ज्ञात हो कि इससे पहले दिग्विजय सिंह से कर्नाटक और गोवा से भी पार्टी प्रभारी का पद वापस ले लिया गया था। इन राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाने में विफल रही थी।

असम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को 2350 करोड़ का राहत पैकेज

नई दिल्ली

पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के बाढ़ग्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग असम के गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने आपदाग्रस्त राज्यों को जरुरी सामान उपलब्ध कराने समेत राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद असम के वित्तमंत्री हिमंतबिस्व सरमा ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए 2,350 करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का वादा किया है।

समीक्षा बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाल, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह समेत नागालैंड के सीएम मौजूद थे। असम में इस साल बाढ़ से 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हाल ही में केंन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने असम के बाढ़ प्रभावित ज़िलों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने असम दौरे से पहले बाढ़ में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था, जिसके तहत असम और राजस्थान में बाढ़ में मरने वाले लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा और बाढ़ में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार दिए जाने की घोषणा की थी।

देश के ज्यादातर राज्य इस समय भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात से लेकर असम तक पानी कहर बरपा रहा है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

अलगाववादी बदल रहे फंडिंग का तरीका - जेटली

नई दिल्ली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को बताया कि कैसे अलगावबादी अपना फंडिंग का तरीका बदल रहे हैं। जेटली ने इसके साथ ही कहा कि नोटबंदी से आतंकी फंडिंग पर रोक लगी है। नोटबंदी के बाद आतंकियों को फंड इकठ्ठा करने के लिए लूट के अलग-अलग तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। नोटबंदी की वजह से आतंकियों का पैसा खत्म हुआ है और बैंक लूट जैसी वारदात को अंजाम देने लगे हैं।

नोटबंदी से पत्थरबाजों की संख्या में भी कमी आई है। जेटली ने बताया कि पिछले 6 महीनों में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन हुर्रियत के बाद एनआइए ने अब तक 8 हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी की है। इन्हें इसी महीने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद शिक्षामित्रों का आंदोलन स्थगित

लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट के शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन के फैसले को रद्द करने के बाद से आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद उसको समाप्त करने का निर्णय किया है। करीब तीन घंटे तक सीएम ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की। वार्ता के समय बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल भी मौजूद थीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल के साथ शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल की भेंट अपना रंग दिखा गई। करीब तीन घंटे की इस बैठक के बाद शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद अपना अंदोलन एक हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब शिक्षामित्र स्कूल जाकर अपना काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने इनके प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह इस बाबत प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। शिक्षामित्रों का आंदोलन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको आंदोलन खत्म करने का सुझाव दिया था। सीएम ने इनसे पठन पाठन का काम शुरु करने को कहा है। इस बात पर शिक्षामित्र राजी हो गए हैं। इन सभी ने प्रदेश में चल रहा आंदोलन एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। शिक्षामित्र आज बुधवार से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देंगे। इन सभी ने एक हफ्ते के लिए प्रदर्शन तथा आंदोलन को टाल दिया है। इन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में भी कोई ठोस नीति नहीं बनी तो प्रदेश में फिर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। इनके बेसिक शिक्षामंत्री अनुपमा जयसवाल ने भी समय मांगा है। अब प्रस्ताव तैयार करने के बाद उसको कैबिनेट में लाने की तैयारी है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने कहा कि सरकार पर हमको भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस भेंट से पहले माना जा रहा था मुख्यमंत्री इनको थोड़ी राहत देने का फैसला भी ले सकते हैं। भेंट के बाद अनुपमा जायसवाल ने कहा कि शिक्षामित्रों को हम हफ्ता या फिर पंद्रह दिन में कोई न कोई अच्छी खबर जरूर देंगे। इनके मामले में सरकार कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी।

इनको कोई भी गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शिक्षामित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कार्यालय, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में भेंट की। यह मुलाकात करीब तीन घंटे तक चली थी। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षामित्र बीते पांच दिन से जगह जगह पर काफी आंदोलन कर रहे हैं। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

पटना

उच्चतम न्यायालय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिये मंगलवार को सहमत हो गया। याचिका में कुमार पर कथित तौर पर लंबित आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम एल शर्मा के मामले की तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर कहा कि वह इसे देखेगी।

नीतीश के खिलाफ आपराधिक मामला होने का आरोप

सोमवार को दायर की गयी याचिका में आरोप लगाया है कि जदयू नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला है। इसमें वह वर्ष 1991 के बाढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से पहले स्थानीय कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या और चार अन्य लोगों को घायल करने के मामले में आरोपी हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से सीबीआई को इस मामले में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, प्रतिवादी संख्या दो (चुनाव आयोग) ने कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी होने के बावजूद उनकी सदन की सदस्यता रद्द नहीं की और प्रतिवादी आज तक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं।

अधिवक्ता ने चुनाव आयोग के वर्ष 2002 के आदेश के अनुसार कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा भी देना पड़ता है।

उन्होंने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2012 को छोड़कर वर्ष 2004 के बाद कभी भी अपने खिलाफ लंबित मामले की जानकारी नहीं दी।

राज्यसभा में बढ़ी सरकार की परेशानी

नई दिल्ली

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मामला फिर अटक गया है। कई मंत्रियों की गैरहाजिरी के कारण विपक्ष राज्यसभा में संशोधन प्रस्ताव पारित करवाने में कामयाब हो गया।

विपक्ष ने नियम तीन को विधेयक से हटवाने के बाद ही अपनी सहमति प्रदान की। सदन ने विपक्ष के संशोधनों के साथ विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक अब वापस लोकसभा को भेजा जाएगा। 123वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना है।

विपक्ष की ओर से लाए गए इन संशोधनों में धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात की गई। अपनी संख्या बल के आधार पर विपक्ष ने इस संशोधन को पारित करा लिया। सरकार का साफ कहना था कि ऐसा कोई भी संशोधन आयोग को कानूनी तौर पर कमजोर कर देगा और यह अदालत में नहीं टिक पाएगा। जाहिर है कि अब सरकार को नए सिरे से तैयारी करके लोकसभा में बिल लाना होगा। ऐसे में आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की पुरानी मांग अटक जाएगी। यह बिल लोकसभा में पहले से ही पारित हो चुका है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक को पारित कराने के लिए 245 सदस्यीय सदन में मौजूद सांसदों में से दो तिहाई का इसके हक में होना जरूरी था, लेकिन कई मंत्रियों की गैरहाजिरी ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी। मतदान के समय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह और बीके हरिप्रसाद ने तीसरे अनुच्छेद में संशोधन की मांग उठाई। पहला संशोधन आयोग के सदस्यों की संख्या को लेकर था।

विपक्ष तीन के बजाय पांच सदस्य पर जोर दे रहा था। दूसरे में राज्यों के हितों को सुरक्षित रखने की बात थी। सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि सरकार प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जुमलों की सरकार है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विपक्ष का संशोधन 52 के मुकाबले 74 वोट से पारित हो गया। भाजपा के लिए यह असहज स्थिति थी, क्योंकि जदयू को मिलाकर सदन में उसके 89 सदस्य हैं। एक बार संशोधन पारित हो गए तो सरकार के लिए पीछे हटने की जगह नहीं रह गई। कुछ सदस्यों का कहना था कि अगर विधेयक पारित नहीं होता है, तो पिछड़े वर्ग को निराशा होगी। दस मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

भारत और सोमालिया के बीच डील, कैदियों की होगी अदला-बदली

नई दिल्ली

भारत इन दिनों अफ्रीकी देशों के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। मंगलवार को भारत और सोमालिया ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देशों के दंडित व्यक्तियों का भारत और सोमालिया में ट्रांसफर किया जाएगा। भारत के दौरे पर आए सोमालिया के विदेश मंत्री युसूफ गराड उमर और सुषमा स्वराज के साथ हुई बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा मानवीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत और सोमालिया ने दंडित व्यक्तियों के ट्रांसफर वाले द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के न्योते पर सोमालियाई विदेश मंत्री उमर पांच दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार को पहुंचे थे। साल की शुरुआत में विदेश मंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है। गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जून में इन समझौतों पर अपनी मुहर लगा दी थी।